

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 18-02-2026

विषय सूची

भारत और फ्रांस द्वारा अपने संबंध विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोजगार योग्यता (Employability) का भविष्य तंबाकू कर सुधारों के माध्यम से जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ करना गैर-अधिसूचित जनजातियों के लिए पृथक वर्गीकरण

संक्षिप्त समाचार

5G युग में नेट न्यूट्रॉलिटी पर पुनर्विचार

भारत-आयरलैंड डिजिटल साझेदारी

SAHI और BODH पहलों का शुभारंभ

एआई-प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया

बी(Bee) कॉरिडोर

गैस टरबाइन इंजन

इंडिया एआई समिट: सेना का स्वदेशी एआई सूट

ब्लैक बॉक्स

मालाबार पाइड हॉन्निबिल

आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

भारत और फ्रांस द्वारा अपने संबंध विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत

संदर्भ

- फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए, जहाँ उन्होंने एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लिया।

प्रमुख परिणाम

- प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' की स्थापना की घोषणा की।
- भारत और फ्रांस ने छठे भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद में रक्षा सहयोग समझौते को आगामी 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया।
- उन्नत साझेदारी और होराइजन 2047 रोडमैप के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा हेतु वार्षिक विदेश मंत्रियों संवाद की स्थापना।
- भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष और भारत-फ्रांस नवाचार नेटवर्क का शुभारंभ।
- कर्नाटक के वेमगल में H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन।
- बीईएल और सफ्रान के बीच संयुक्त उद्यम, जिसके अंतर्गत भारत में HAMMER मिसाइलों का उत्पादन होगा।
- भारत ने फ्रांस से राफेल में 'स्वदेशी सामग्री' को 50% तक बढ़ाने और भारत में राफेल के मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल सुविधा का विस्तार करने का अनुरोध किया।
- भारतीय सेना और फ्रांसीसी थल सेना प्रतिष्ठानों में अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती।

भारत-फ्रांस संबंधों की प्रमुख विशेषताएँ

- रणनीतिक साझेदारी:** 26 जनवरी 1998 को शुरू हुई, यह भारत की प्रथम रणनीतिक साझेदारी थी।
 - मुख्य दृष्टि:** रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना और द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर करना।
 - प्रमुख स्तंभ:** रक्षा और सुरक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग।

- विस्तारित क्षेत्र:** इंडो-पैसिफिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, उन्नत तकनीकें और आतंकवाद-रोधी प्रयास।
- रक्षा सहयोग:** वार्षिक रक्षा संवाद (मंत्री-स्तर) और उच्च रक्षा सहयोग समिति (सचिव-स्तर) के माध्यम से समीक्षा।
 - राफेल लड़ाकू विमान:** भारत ने 36 राफेल खरीदे।
 - स्कॉर्पिन पनडुब्बियाँ (प्रोजेक्ट P-75):** फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ सहयोग, 6 पनडुब्बियाँ भारत में निर्मित; नवीनतम है आईएनएस वाघशीर।
 - लड़ाकू विमान इंजन विकास:** HAL और सफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन ने IMRH कार्यक्रम के अंतर्गत इंजन सह-विकास समझौता किया।
 - हाल ही में दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-M लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु अंतर-सरकारी समझौता (IGA) किया।
 - भविष्य की योजना:** अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजन का सह-विकास।
 - संयुक्त अभ्यास:** शक्ति, वरुण, FRINJEX-23।
 - आर्थिक सहयोग:** यूरोपीय संघ में फ्रांस भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जो नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और जर्मनी के बाद आता है।
 - 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 15.11 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा।
 - दोनों देश संयुक्त रूप से तकनीक विकसित कर रहे हैं और वर्तमान तकनीकों का एकीकरण कर रहे हैं।
 - फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का सफल कार्यान्वयन।
 - भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, सतत निर्माण और शहरी अवसंरचना में फ्रांसीसी तकनीकों का समावेश।
 - अंतरिक्ष सहयोग:** ISRO और CNES (फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी) के बीच 60 वर्षों से अधिक का सहयोग।
 - फ्रांस प्रमुख घटक और लॉन्च सेवाएँ (Arianespace) प्रदान करता है।

- संयुक्त मिशन: TRISHNA, MDA सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन समर्थन।
- ऊर्जा सहयोग:
 - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा सह-स्थापित।
 - नाभिकीय ऊर्जा सहयोग: 2025 में विशेष कार्यबल की प्रथम बैठक।
 - दोनों पक्ष SMR (छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर) और AMR (उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर) पर साझेदारी के लिए सहमत।
- समुदाय: फ्रांस में लगभग 1,19,000 भारतीय समुदाय रहते हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों से हैं।

चिंताएँ

- व्यापार असंतुलन: द्विपक्षीय व्यापार अपनी संभावनाओं से कम बना हुआ है, विशेषकर भारत के अन्य यूरोपीय संघ देशों के साथ व्यापार की तुलना में।
- तकनीकी हस्तांतरण एवं रक्षा प्रतिबंध: यद्यपि फ्रांस ने भारत के रक्षा लक्ष्यों का समर्थन किया है, फिर भी बड़े रक्षा उपकरणों में तकनीकी हस्तांतरण की गहराई को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- नाभिकीय दायित्व संबंधी चिंताएँ: 2008 में नागरिक नाभिकीय समझौते और जैतापुर में रिएक्टरों की योजना के बावजूद प्रगति धीमी रही है।
 - सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डेमेज एक्ट (2010) फ्रांसीसी कंपनियों के लिए बाधा उत्पन्न करता है क्योंकि यह नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व लागू करता है।
- भूराजनीतिक अंतर: चीन के साथ फ्रांस के सुदृढ़ आर्थिक संबंध कभी-कभी इंडो-पैसिफिक मुद्दों पर भारत के साथ पूर्ण सामंजस्य को कमज़ोर कर देते हैं।
 - मध्य पूर्व की राजनीति के प्रति दृष्टिकोण में भी समय-समय पर अंतर दिखाई देता है।

भविष्य की दिशा

- होराइजन 2047 रोडमैप की परिकल्पना: भारत-फ्रांस साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दोनों देशों ने

- वर्ष 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा निर्धारित करने हेतु एक रोडमैप अपनाने पर सहमति व्यक्त की।
- उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और उत्पादन को प्रोत्साहन।
- संयुक्त रूप से विकसित उत्पादों का वैश्विक हित में तृतीय देशों को निर्यात।
- समुद्री एवं अंतरिक्ष सुरक्षा सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करना।
- रणनीतिक संवाद तथा संयुक्त सैन्य उपस्थिति के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती अभिसरण सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

- भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का आधार है।
- संप्रभुता, बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय स्थिरता में साझा हितों के साथ, दोनों देश होराइजन 2047 दृष्टि के तहत संबंधों को और ऊँचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं — जिससे रक्षा सहयोग अधिक सहयोगात्मक, नवोन्मेषी एवं निर्यात-उन्मुख बनेगा।

स्रोत: TH

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोजगार योग्यता (Employability) का भविष्य

संदर्भ

- भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में “कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में रोजगार योग्यता का भविष्य” पर उच्च-स्तरीय चर्चा आयोजित हुई, जिसमें नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों ने भाग लिया।

परिचय

- चर्चा में यह परखा गया कि स्वचालन के तीव्रता से बढ़ने के बीच कौन-सी कौशल, भूमिकाएँ और मानसिकताएँ प्रासंगिक बनी रहेंगी तथा व्यक्तियों को रोजगारयोग्य बने रहने के लिए क्या करना होगा।

- वक्ताओं ने रचनात्मकता, सिस्टम थिंकिंग, अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखने के महत्व पर बल दिया, जो संकीर्ण कार्य-आधारित विशेषज्ञता से अधिक मूल्यवान हैं।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार ने रेखांकित किया कि तकनीकी अपनाने को जन-रोजगार योग्यता के साथ समर्खित करना एक स्पष्ट राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होना चाहिए।
- यह प्रयास केवल सरकार तक सीमित न रहकर टीम इंडिया पहल बने, जिसमें नीति-निर्माता, उद्योग, शिक्षाविद और समाज सम्मिलित हों।
- विचार-विमर्श ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि एआई बड़े व्यवधान लाता है, यह भारत को एक समावेशी, नवाचार-प्रेरित और उत्तरदायी एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का अवसर भी देता है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं नागरिक कल्याण के अनुरूप हो।

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026

- आयोजक: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
- यह समिट प्रधानमंत्री द्वारा फ्रांस एआई एकशन समिट में घोषित की गई थी और यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई समिट होगा।
- यह मौजूदा बहुपक्षीय पहलों को सुदृढ़ करेगा और नई प्राथमिकताओं, परिणामों तथा सहयोगी ढाँचों को आगे बढ़ाएगा।
- तीन सूत्र: लोग, ग्रह और प्रगति — ये तीन आधारभूत स्तंभ परिभाषित करते हैं कि बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से एआई को सामूहिक लाभ हेतु कैसे दोहन किया जा सकता है।



भारत में रोजगारों पर एआई का प्रभाव

- सामान्य, दोहराव वाले कार्य सबसे अधिक प्रभावित: BPO/कस्टमर सर्विस, बुनियादी लिपिकीय कार्य, असेंबली-लाइन कार्य और नियमित लॉजिस्टिक्स जैसी भूमिकाएँ एआई-आधारित स्वचालन से काफी कम हो सकती हैं।
- पारंपरिक मध्यम-कौशल रोजगार: जो स्थिर रोजगार देती थीं, अब स्वचालन के कारण दबाव में हैं।
- आईटी और आउटसोर्सिंग: एआई उपकरण कोडिंग, परीक्षण और सपोर्ट कार्य संभाल रहे हैं, जिससे प्रमुख आईटी कंपनियों और आउटसोर्सिंग फर्मों में कार्यबल पुनर्गठन हो रहा है।

उभरते अवसर

- नई तकनीकें ऐसे रोजगार सृजित कर रही हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, जैसे: एआई/एमएल इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और विश्लेषक, क्लाउड आर्किटेक्ट, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, एआई प्रोडक्ट मैनेजर एवं प्रॉम्प्ट इंजीनियर।
 - ये भूमिकाएँ उच्च वेतन प्राप्त करती हैं और इनकी मांग तीव्रता से बढ़ रही है।
 - अनुमान है कि आगामी कुछ वर्षों में लाखों नए टेक रोजगार जुड़ेंगे; केवल भारत में 2027 तक लगभग 4.7 मिलियन एआई/टेक भूमिकाएँ उभर सकती हैं।
- कौशल मांग में परिवर्तन:** 2030 तक भारत की लगभग 38% कार्यबल को कौशल आवश्यकताओं में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, जो BRICS देशों में सबसे अधिक है।
 - पारंपरिक शैक्षणिक प्रमाणपत्र रोजगार योग्यता के कम संकेतक बन रहे हैं; भर्तीकर्ता तकनीकी कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता और अनुकूलनशील सीखने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

आगे की राह

- अपस्किलिंग और रिस्किलिंग की आवश्यकता:** भारत को बड़े पैमाने पर पुनःकौशल की आवश्यकता है; अनुमान है कि 2027 तक 1.6 करोड़ से अधिक श्रमिकों को एआई और स्वचालन तकनीकों में पुनःकौशल की आवश्यकता होगी।
- सरकार और उद्योग की पहलें:** राष्ट्रीय रणनीतियाँ और साझेदारियाँ छात्रों एवं श्रमिकों को एआई तथा तकनीकी दक्षताओं से सक्षम बनाने पर केंद्रित हैं।
 - बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट कौशल-निर्माण पहलें कार्यबल की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए चल रही हैं।

निष्कर्ष

- यद्यपि कुछ पारंपरिक भूमिकाएँ घटेंगी या परिवर्तित होंगी, नई संभावनाओं का एक गतिशील परिदृश्य खुल रहा है जो उन्नत तकनीकी क्षमताओं, सतत सीखने और अनुकूलनशीलता को पुरस्कृत करता है।

- इस संक्रमण के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा प्रणाली के समन्वित प्रयास आवश्यक होंगे ताकि भारत का कार्यबल भविष्य के कार्य के लिए तैयार हो सके।

सरकारी पहलें

- फ्यूचरस्किल्स(FutureSkills) PRIME (राष्ट्रीय पुनःकौशल एवं अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म):** MeitY और NASSCOM की साझेदारी में एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो आईटी पेशेवरों और युवाओं को एआई सहित 10 नई एवं उभरती तकनीकों में कौशल प्रदान करता है।
- स्किल इंडिया मिशन:भारत का व्यापक 'स्किल इंडिया मिशन' अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित अनेक घटकों को समाहित करता है।

 - यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी कौशलों के प्रारंभिक परिचय को प्रोत्साहित करता है तथा व्यावसायिक मार्गों को भविष्य की प्रौद्योगिकी आधारित भूमिकाओं में रोजगार योग्यता से संबद्ध करता है।**
- NCVET:** नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (NPAI) स्किलिंग फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो एआई, डेटा विज्ञान और उभरती तकनीकों में कौशल के लिए राष्ट्रीय रोडमैप, संरचना एवं दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है।
- SOAR पहल:** एमएसडीई द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य स्कूल छात्रों (कक्षा 6–12) में एआई जागरूकता और बुनियादी कौशल स्थापित करना तथा शिक्षकों में एआई साक्षरता विकसित करना है।
- DGT सहयोग:** IBM इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एडोबी इंडिया, AWS आदि के साथ CSR के तहत कौशल पहलें।
- सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs):** उद्योग और वैश्विक विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी से पाठ्यक्रम सह-विकसित करते हैं एवं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स आयोजित करते हैं।
 - अग्रणी उद्योग साझेदार पाठ्यक्रम समर्थन और एआई, रोबोटिक्स तथा क्लाइमेट टेक में अंत्रिसिशिप/इंटर्नशिप प्रदान करते हैं।

स्रोत: PIB

तंबाकू कर सुधारों के माध्यम से जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ करना

संदर्भ

- भारत, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और उपभोक्ता है, गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य भार का सामना कर रहा है क्योंकि सिगरेट कर खुदरा मूल्य का केवल लगभग 53% ही बनाते हैं, जो WHO मानक से काफी कम है।

तंबाकू के बारे में

- तंबाकू एक वाणिज्यिक फसल है जो मुख्यतः निकोटियाना टैबैकम पौधे से प्राप्त होती है, जिसकी पत्तियों में निकोटीन होता है — यह एक अत्यधिक नशे का व्यसन उत्पन्न करने वाला एल्कलॉइड है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है।
- इसका उपयोग धूम्रपान रूपों (सिगरेट, सिगार, बीड़ी) और बिना धूम्रपान रूपों (गुटखा, खैनी, चबाने वाला तंबाकू) में किया जाता है।

भारत में तंबाकू का स्वास्थ्य बोझ

- तंबाकू उपयोग से भारत में प्रति वर्ष लगभग 13.5 लाख मृत्युएँ होती हैं, जिनका कारण कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों के विकार और स्ट्रोक है।
- निकोटीन अत्यधिक नशे का व्यसन उत्पन्न करता है और मस्तिष्क के डोपामिनर्जिक रिवार्ड सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे इसे छोड़ना कठिन हो जाता है।
 - मैंथॉल जैसे एडिटिव्स निकोटीन को लंबे समय तक बनाए रखते हैं और व्यसन की संभावना बढ़ाते हैं।
- प्लास्टिक फिल्टर वाले सिगरेट बट्स पर्यावरण प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावित होता है।
- WHO के एक अध्ययन के अनुसार, भारत तंबाकू उपयोग से होने वाली बीमारियों और समयपूर्व मृत्युओं के कारण अपने GDP का 1% खो देता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण के रूप में कराधान

- WHO मानक:** WHO अनुशंसा करता है कि कर खुदरा मूल्य का कम से कम 75% होना चाहिए ताकि तंबाकू उपभोग को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।

- उच्च कराधान से वहनीयता घटती है, विशेषकर युवाओं और निम्न-आय वर्गों में, जो मूल्य-संवेदनशील होते हैं।

- भारतीय परिदृश्य:** वर्तमान में सिगरेट कर खुदरा मूल्य का केवल 53% है।
 - सिगरेट और बिना धूम्रपान तंबाकू पर GST 40% है, साथ ही अतिरिक्त उपकर भी लगाया गया है।
 - हालांकि, बीड़ी पर GST घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि यह निम्न-आय वर्गों में अत्यधिक प्रचलित है।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- तंबाकू नियंत्रण पर रूपरेखा अभियान (FCTC):** भारत WHO द्वारा 2005 में शुरू किए गए FCTC का हस्ताक्षरकर्ता है।
 - इसका उद्देश्य मांग और आपूर्ति में कमी की रणनीतियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर तंबाकू उपयोग को कम करना है।
 - अनुच्छेद 5.3 के अंतर्गत, अभियान पक्षकारों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व देता है कि जनस्वास्थ्य नीतियों को उद्योग के वाणिज्यिक हितों से सुरक्षित रखा जाए।
- COTPA 2003:** सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में उत्पादन, विज्ञापन, वितरण और उपभोग को नियंत्रित करने वाले 33 प्रावधान हैं।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP):** 2007 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य COTPA और FCTC के कार्यान्वयन में सुधार करना, तंबाकू उपयोग के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसे छोड़ने में सहायता करना है।
- ई-सिगरेट निषेध विधेयक, 2019:** ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।

शासन संबंधी चुनौतियाँ

- उद्योग हस्तक्षेप:** WHO FCTC ने बार-बार नीति-निर्माण में तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप को चिन्हित किया है।

- **नीतिगत असंगतियाँ:** सिंगरेट पर 40% और बीड़ी पर 18% GST दरें असमानता उत्पन्न करती हैं तथा स्वास्थ्य समानता लक्ष्यों को कमज़ोर करती हैं।
 - अपर्याप्त मुद्रास्फीति समायोजन कर वृद्धि के वास्तविक प्रभाव को कम कर देता है।
- **पैकेजिंग दिशानिर्देशों का उल्लंघन:** बिना धूम्रपान तंबाकू उत्पाद प्रायः COTPA पैकेजिंग दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं; अध्ययनों में पाया गया कि 92.8% पैकेजों में अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं होती।

आगे की राह

- तंबाकू कराधान को WHO के 75% मानक के अनुरूप करना चाहिए ताकि वहनीयता कम हो सके।
- स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने के लिए बीड़ी और बिना धूम्रपान तंबाकू पर कर बढ़ाकर GST को तर्कसंगत बनाया जाए।
- नीति-निर्माण को उद्योग हस्तक्षेप से बचाने के लिए FCTC अनुच्छेद 5.3 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- तंबाकू अपशिष्ट के लिए पर्यावरणीय जवाबदेही को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढाँचों के तहत एकीकृत किया जाए।

स्रोत: TH

गैर -अधिसूचित जनजातियों के लिए पृथक वर्गीकरण

समाचार में

- केंद्र सरकार ने गैर -अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के नेताओं को आश्वासन दिया है कि उन्हें 2027 की जनगणना के दूसरे चरण में गिना जाएगा, लेकिन प्रक्रिया के विवरण अभी स्पष्ट नहीं हैं।

गैर -अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ

- इन जनजातियों को औपनिवेशिक शासन के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट (CTA), 1871 के अंतर्गत “अपराधी” करार दिया गया था, जिसमें कुछ समुदायों

को जाति-आधारित वंशानुगत अपराध प्रवृत्ति वाला माना गया।

- इस अधिनियम ने इन तथाकथित अपराधी जनजातियों के पंजीकरण, निगरानी और नियंत्रण की अनुमति दी।
- CTA को 1952 में निरस्त कर दिया गया, जिससे इन समुदायों को आधिकारिक रूप से डीनोटिफाई किया गया और गैर -अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की श्रेणी बनाई गई।
- हालांकि उसी वर्ष राज्यों ने हैबिचुअल ऑफेंडर लॉज लागू किए, जिन्होंने वंशानुगत अपराधिता को हटाते हुए भी इन समुदायों को “आदतन अपराधी” के रूप में लक्षित किया और भेदभाव को नए रूप में जारी रखा।

गणना

- इन जनजातियों की गणना 1911–1931 की जनगणनाओं में की गई थी। CTA निरस्तीकरण के बाद, गैर -अधिसूचित समुदायों को बड़े पैमाने पर SC, ST या OBC सूचियों में शामिल किया गया। राष्ट्रीय आयोगों ने बाद में DNTs को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए एक समर्पित जनगणना की आवश्यकता पर बल दिया।
- **रेणके आयोग (2008):** प्रथम राष्ट्रीय निकाय जिसने DNT समुदायों की सूची बनाई।
- **इदाते आयोग (2014–2017):** लगभग 1,200 समुदायों की पहचान की जो SC/ST/OBC श्रेणियों में समाहित थे और 268 समुदायों को अवर्गीकृत पाया।
- **भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण (AnSI):** इन 268 समूहों का अध्ययन किया और उन्हें वर्तमान अनुसूचित सूचियों में शामिल करने की सिफारिश की, लेकिन कार्यान्वयन धीमा रहा।

मुद्दे और चिंताएँ

- **सामाजिक कलंक:** DNTs, यद्यपि कई राज्यों में SC, ST और OBC सूचियों में शामिल हैं, फिर भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हाशिए पर बने हुए हैं। इसका कारण आंशिक रूप से हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट जैसी कानूनों और लंबे समय से चले आ रहे कलंक हैं।

- **दस्तावेजीकरण की कमी:** अस्पष्ट वर्गीकरण के कारण कई समुदाय जाति-आधारित आरक्षण से बाहर रह जाते हैं।
- **आर्थिक असुरक्षा:** पारंपरिक आजीविकाएँ (लोककला, पशुपालन, घुमंतू व्यापार) घट गई हैं, जिससे वे निर्धनता का सामना कर रहे हैं।
- **शिक्षा अंतराल:** उच्च निरक्षरता और औपचारिक शिक्षा तक कम पहुँच।
- **राजनीतिक अदृश्यता:** विश्वसनीय जनगणना डेटा की अनुपस्थिति और नीति-निर्माण में कमजोर प्रतिनिधित्व।

सरकारी कदम

- **राष्ट्रीय आयोग (2014):** DNT समुदायों की पहचान की और कल्याणकारी उपायों की सिफारिश की।
- **DNTs के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (2019):** योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों की देखरेख हेतु स्थापित।
- सामाजिक न्याय विभाग ने DNT/NT/SNT के विकास एवं कल्याण हेतु 'गैर-अधिसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (SEED)' नामक एक योजना का निर्माण किया है।
 - यह योजना DNT समुदायों को शिक्षा (कोचिंग), स्वास्थ्य (आयुष्मान कार्ड), आजीविका (स्वयं सहायता समूह) तथा आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाएँ) के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है।
- अन्य कार्यक्रमों में DNT के लिए डॉ. आंबेडकर पूर्व-मैट्रिक एवं पश्चात-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ष 2014-15 से) तथा DNT विद्यार्थियों के लिए नानाजी देशमुख छात्रावास योजना सम्मिलित हैं।

स्रोत :TH

संक्षिप्त समाचार

5G युग में नेट न्यूट्रॉलिटी पर पुनर्विचार

संदर्भ

- रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों ने सरकार से भारत के 2016 के नेट न्यूट्रॉलिटी

ढाँचे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है ताकि 5G नेटवर्क के अंतर्गत 'नेटवर्क स्लाइसिंग' को स्पष्ट रूप से अनुमति दी जा सके।

नेट न्यूट्रॉलिटी क्या है?

- नेट न्यूट्रॉलिटी वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी इंटरनेट ट्रैफिक को समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के — चाहे वह सामग्री, प्लेटफॉर्म, एप्लिकेशन या उपयोगकर्ता पर आधारित हो।
- यह निषेध करता है:
 - वैध सामग्री को ब्लॉक करना।
 - श्रॉटलिंग (विशिष्ट सेवाओं को जानबूझकर धीमा करना)।
 - कुछ ऐप्स या वेबसाइटों को भुगतान आधारित प्राथमिकता देना।
- भारत ने 2016-2018 में सार्वजनिक परिचर्चाओं के बाद विश्व के सबसे सशक्त नेट न्यूट्रॉलिटी ढाँचों में से एक को अपनाया।

नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है?

- नेटवर्क स्लाइसिंग 5G की एक विशेषता है जो एक ही भौतिक अवसंरचना पर कई वर्चुअल नेटवर्क बनाने की अनुमति देती है।
- प्रत्येक "स्लाइस" को विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है:
 - अत्यंत कम विलंबता (स्वायत्त वाहन, टेलीमेडिसिन)।
 - उच्च विश्वसनीयता (औद्योगिक स्वचालन)।
 - उच्च बैंडविड्थ (गेमिंग, एचडी स्ट्रीमिंग)।
- दूरसंचार ऑपरेटरों का तर्क है कि यह 5G की अंतर्निहित तकनीकी क्षमता है, न कि सामग्री-आधारित भेदभाव। वे चाहते हैं:
 - सेवा गुणवत्ता (QoS) में भिन्नता प्रदान करना।
 - गारंटीकृत गति या कम विलंबता के लिए प्रीमियम मूल्य वसूलना।

स्रोत: ET

भारत-आयरलैंड डिजिटल साझेदारी

संदर्भ

- भारत और आयरलैंड ने नई दिल्ली में उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठक आयोजित की ताकि दूरसंचार, डिजिटल अवसंरचना और उभरती तकनीकों में सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- भारत का डिजिटल परिवर्तन:** भारत ने ICT और डिजिटल शासन में अपनी उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं।
 - विश्व के सबसे बड़े डिजिटल पारिस्थितिक तंत्रों में से एक, जिसमें 1.23 अरब से अधिक दूरसंचार ग्राहक और लगभग एक अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं।
 - 5G कवरेज लगभग 99.9% जिलों तक फैला हुआ है, जहाँ डेटा टैरिफ औसतन USD 0.10 प्रति GB है, जिससे कनेक्टिविटी सुलभ बनी है।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** भारत ने UPI, DBT, DigiLocker, Digi Yatra और संचार साथी जैसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्मों को उजागर किया।

आयरलैंड के बारे में

- आयरलैंड उत्तर-पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, जो आयरिश सागर द्वारा ग्रेट ब्रिटेन से अलग है।
- भू-आकृति:** एक केंद्रीय निम्नभूमि चूना-पत्थर का मैदान, जो तटीय पर्वतों से घिरा है।



- उदाहरण:** मैकगिलीकडी की रीक्स(दक्षिण-पश्चिम में)।
- नदी और झीलें:** रिवर शैनन सबसे लंबी नदी है। प्रमुख झीलों में लॉफ नेघ और लॉफ कोरिब शामिल हैं।
- राजधानी:** डबलिन।

स्रोत: PIB

SAHI और BODH पहलों का शुभारंभ

संदर्भ

- भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान दो डिजिटल स्वास्थ्य पहलें शुरू कीं — SAHI (स्वास्थ्य पहल के लिए सुरक्षित एआई) और BODH (हेल्थ AI के लिए ओपन डेटा प्लेटफॉर्म की बेंचमार्किंग)।

विवरण

- SAHI:**
 - यह एक शासन ढाँचा, नीतिगत मार्गदर्शक और राष्ट्रीय रोडमैप है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करता है।
 - इसका उद्देश्य एआई का उपयोग नैतिक, पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित तरीके से करना है।
 - यह प्लेटफॉर्म ज्ञान-साझाकरण और शासन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा, स्वास्थ्य एआई विकास एवं कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देगा।
- BODH:**
 - इसे IIT कानपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है।
 - यह विविध, गुमनाम वास्तविक स्वास्थ्य डेटा सेट का उपयोग करके एआई मॉडलों का व्यवस्थित मूल्यांकन सक्षम करेगा।
 - बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले एआई समाधानों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है।

सामूहिक महत्व:

- SAHI और BODH मिलकर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि वह एक विश्वसनीय, समावेशी और वैश्विक

प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है, जो नवाचार, जिम्मेदारी एवं जन-विश्वास पर आधारित है।

स्रोत: TH

एआई-प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया

समाचार में

- अटल इनोवेशन मिशन ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 'एआई-प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया' का शुभारंभ किया, जो भारत के उद्देश्य-प्रेरित एआई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करता है।

एआई-प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के बारे में

- यह एक प्रमुख कॉफी टेबल बुक है, जिसमें 45 अग्रणी एआई स्टार्टअप्स की यात्राओं का विवरण है, जो वास्तविक विश्व की चुनौतियों के समाधान तैयार कर रहे हैं।
- इसमें 30+ क्षेत्रीय डोमेनों में कार्यरत स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है, जैसे: स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत विकास, गतिशीलता, खेल विश्लेषण, डीप टेक एवं सामाजिक प्रभाव।
- यह पुस्तक भारत के एआई नवाचार परिदृश्य की भौगोलिक और विषयगत विविधता को दर्शाती है, जो पारंपरिक तकनीकी केंद्रों से कहीं आगे तक फैली है।

उद्देश्य

- यह पुस्तक प्रदर्शित करती है कि सार्वजनिक नवाचार अवसंरचना, सतत इन्क्यूबेशन समर्थन और मिशन-आधारित शासन कैसे भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक महत्व के साथ स्केलेबल प्रभाव देने में सक्षम बना रहे हैं।
- एआई-प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया भारत को केवल अग्रणी तकनीकों का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि उत्तरदायी एआई मार्गों को आकार देने वाला वैश्विक योगदानकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है।
- यह समावेशी विकास और नैतिक परिनियोजन के लिए भारत की एआई दृष्टि को सुदृढ़ करता है।

स्रोत: PIB

बी (Bee) कॉरिडोर

समाचार में

- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ समर्पित 'बी कॉरिडोर' बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है।

परिचय

- इस पहल का उद्देश्य मधुमक्खियों के अनुकूल बनस्पति की सतत रैखिक पट्टियाँ स्थापित करना है, जिसमें सावधानीपूर्वक चयनित फूलदार पेड़ और पौधे लगाए जाएँगे।
- पारंपरिक सजावटी पौधारोपण के विपरीत, नए कॉरिडोर इस प्रकार डिज़ाइन किए जाएँगे कि वे पूरे वर्ष अमृत और पराग प्रदान करें, जिससे परागणकर्ताओं के लिए निरंतर खाद्य स्रोत सुनिश्चित हो।
- NHAI वर्ष 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगभग 40 लाख पेड़ लगाने की योजना बना रहा है, जिनमें से लगभग 60% 'बी कॉरिडोर' पहल के अंतर्गत लगाए जाएँगे।

महत्व

- यह पहल मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं द्वारा झेले जा रहे बढ़ते पारिस्थितिक तनाव को कम करने में सहायता करेगी।
- इससे परागण सेवाओं, कृषि और बागवानी उत्पादकता तथा समग्र पारिस्थितिक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्रोत: IE

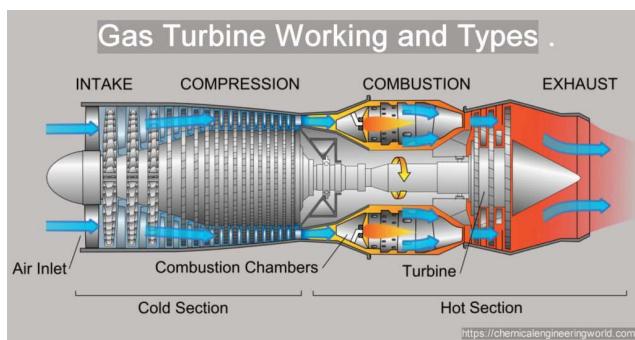
गैस टरबाइन इंजन

समाचार में

- रक्षा मंत्री ने बैंगलुरु स्थित DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्ट्रॉबिलिशमेंट (GTRE) का दौरा किया, जहाँ उन्होंने स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनमें कावेरी इंजन आप्टरबनर टेस्ट भी शामिल है।

गैस टरबाइन इंजन

- गैस टरबाइन इंजन एक आंतरिक दहन इंजन है, जो वायु और ईंधन का उपयोग करके टरबाइन को घुमाकर शक्ति उत्पन्न करता है।
- इसमें कंप्रेसर, दहन कक्ष और टरबाइन होते हैं, जहाँ वायु को संपीड़ित किया जाता है, ईंधन को स्थिर दबाव पर जलाया जाता है और अतिरिक्त वायु गैसों को ठंडा करती है, इससे पहले कि वे टरबाइन तक पहुँचें।
- गैस टरबाइन का उपयोग विमान (जेट प्रणोदन), विद्युत उत्पादन और पाइपलाइनों के लिए कंप्रेसर चलाने में किया जाता है।
- प्रथम सफल गैस टरबाइन 1903 में पेरिस में बनाया गया था।



स्रोत: PIB

इंडिया एआई समिट: सेना का स्वदेशी एआई सूट

संदर्भ

- इंडिया एआई समिट में भारतीय सेना ने स्वदेशी एआई-आधारित समाधानों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की, जिनका रक्षा और नागरिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण द्विउपयोग संभावित है।

प्रमुख विशेषताएँ

- AI एज्जामिनर:** शिक्षा और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्मों के लिए स्वचालित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रणाली।
- SAM-UN:** भू-स्थानिक और एआई-सक्षम स्थितिजन्य जागरूकता प्लेटफॉर्म, मिशन योजना, आपदा प्रतिक्रिया और स्मार्ट कमांड केंद्रों हेतु।

- EKAM (AI-as-a-Service):** सुरक्षित, एयर-गैर्ड स्वदेशी एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करता है।
- PRAKSHEPAN:** एआई-चालित जलवायु विज्ञान और आपदा पूर्वानुमान प्रणाली, भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन के लिए अग्रिम चेतावनी प्रदान करती है।
- XFace:** सुरक्षा और पहचान सत्यापन हेतु एआई आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली।
- नभ दृष्टि:** मोबाइल टेलीमेट्री आधारित वास्तविक समय रिपोर्टिंग और दृश्यांकन प्लेटफॉर्म।
- ड्राइवर फ्रटीग डिटेक्शन:** वास्तविक समय में उनींदापन अलर्ट देने वाला एआई उपकरण।
- AI-in-a-Box:** दूरस्थ या असंबद्ध वातावरण में सुरक्षित परियोजन हेतु पोर्टेबल एज एआई प्लेटफॉर्म।
- बाहन ट्रैकिंग प्रणाली:** एआई-सक्षम बेड़ा निगरानी और लॉजिस्टिक्स अनुकूलन।
- डीपफेक डिटेक्शन और एआई साइबर सुरक्षा प्रणाली:** सिंथेटिक मीडिया, मैलवेयर, साइबर खतरों का सामना करने और महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की रक्षा हेतु उपकरण।



महत्व

- ये पहले एक सुरक्षित, नेटवर्क-सक्षम और एआई-सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र की ओर निर्णायिक बदलाव को दर्शाती हैं, जो रक्षा तैयारी को मजबूत करने के साथ-साथ आपदा लचीलापन, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास को भी बढ़ावा देती हैं।

स्रोत: TH

ब्लैक बॉक्स

संदर्भ

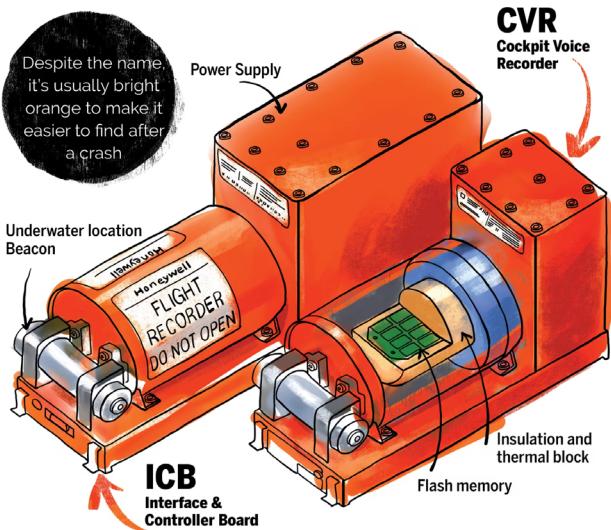
- एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने लियरजेट 45 विमान से ब्लैक बॉक्स बरामद किया, जो बरामती में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जिसमें पाँच लोगों की मृत्यु हुई।

ब्लैक बॉक्स क्या है?

- ब्लैक बॉक्स एक छोटा उपकरण है जो विमान की उड़ान के दौरान उससे संबंधित जानकारी रिकॉर्ड करता है।
- यह चमकीले नारंगी या पीले रंग का आयताकार बॉक्स होता है, जिसे विस्फोट, आग, जल दबाव और उच्च गति दुर्घटनाओं को सहने योग्य बनाया जाता है।
- इसका आविष्कार ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने किया था। इसका उपयोग विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में किया जाता है।

Black Box

A black box in aviation refers to a pair of flight recorders that capture key flight information. They are critical for investigations following an aircraft crash



ब्लैक बॉक्स क्या करता है?

- ब्लैक बॉक्स दो घटकों से मिलकर बना होता है:
 - कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR):** कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें पायलट वार्तालाप, अलार्म और इंजन ध्वनियाँ शामिल होती हैं।

- फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR):** प्रमुख उड़ान मानकों को लॉग करता है, जैसे ऊँचाई, वायु गति, उड़ान दिशा, ऊर्ध्वाधर त्वरण, पिच और रोल कोण आदि।
- स्थान:** दोनों रिकॉर्डर सामान्यतः विमान के टेल सेक्शन में लगाए जाते हैं, जो सांख्यिकीय रूप से दुर्घटनाओं में सबसे कम प्रभावित क्षेत्र होता है।
- दुर्घटना जीवित रहने की क्षमताएँ**
 - सामग्री:** टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील आवरण।
 - प्रभाव प्रतिरोध:** 3,400 g बल तक सहन कर सकता है।
 - आग प्रतिरोध:** 1,100°C तापमान को कम से कम 60 मिनट तक सहन कर सकता है।
 - दबाव प्रतिरोध:** 6,000 मीटर तक की गहराई में समुद्री दबाव सहन कर सकता है।

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB)

- स्थापना:** 2012, नागरिक उड़ान मंत्रालय के अंतर्गत।
- अधिदेश:** नागरिक विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच करना, कारणों का निर्धारण करना और सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना (ICAO के Annex 13 के अनुसार)।
- कानूनी आधार:** वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017।

स्रोत: IE

मालाबार पाइड हॉर्नबिल

समाचार में

- छत्तीसगढ़ वन विभाग उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए स्थायी आवास उपलब्ध कराने और वन पुनर्जनन को बढ़ावा देने हेतु छह “हॉर्नबिल रेस्टोरेंट” स्थापित कर रहा है।

मालाबार पाइड हॉर्नबिल (एंथ्राकोसेरोस कोरोनाट्स)

- इसकी ऊँचाई 2 से 2.5 फीट होती है, बड़ा चौंच और आकर्षक पंख होते हैं।

- यह आर्द्र सदाबहार और ऊँचे पर्णपाती वनों, बागानों और निम्न-ऊँचाई वाले नदी किनारे क्षेत्रों में निवास करता है।
- यह मुख्यतः अंजीर पर भोजन करता है और विकसित होने की घटनाओं का अनुसरण करते हुए मौसमी रूप से स्थानांतरित होता है, कभी-कभी खेती वाले क्षेत्रों में अलग-थलग पेड़ों तक भी पहुँचता है।
- इसका वितरण पश्चिमी घाटों में तथा पूर्वी/मध्य भारत में दक्षिण-पश्चिम पश्चिम बंगाल और बिहार से आंध्र प्रदेश तक, साथ ही श्रीलंका में भी होता है।
- इन्हें उष्णकटिबंधीय वनों में कीस्टोन सीड डिस्पर्सर के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- हॉर्नबिल के प्राकृतिक शिकारी तेंदुए, साँप और भारतीय शाहीन फाल्कन हैं, जिनकी जनसंख्या हाल ही में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में बढ़ी है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के नवीनतम आकलन (2024) में मालाबार पाइड हॉर्नबिल को रेड

लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज़’ में ‘नियर थ्रेटेड’ श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया।

स्रोत: IE

आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संदर्भ

- टाइम मैगजीन ने “आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई” को वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, जिसमें सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क, डेमिस हासाबिस जैसे प्रमुख तकनीकी नेताओं को उजागर किया गया।

एआई आर्किटेक्ट क्या है?

- एआई आर्किटेक्ट एक वरिष्ठ तकनीकी पेशेवर होता है, जो किसी संगठन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के विकास और परिनियोजन की रूपरेखा तैयार करता है, योजना बनाता है तथा उसकी देखरेख करता है।
- इस भूमिका में तकनीकी विशेषज्ञता, प्रणाली डिज़ाइन क्षमता और रणनीतिक दृष्टि का संयोजन होता है।

THE WEB OF A.I. LEADERS

A deeply connected network of researchers, mentors and founders is shaping modern AI.

Hundreds of alumni from these two organisations have gone on to found their own startups

OpenAI
SAM ALTMAN

DeepMind
DEMIS HASSABIS

Anthropic



Dario Amodei
Daniela Amodei

Safe
Superintelligence



Ilya Sutskever
co-founder of
OpenAI

Thinking
Machines
Lab



Mira Murati
quit as OpenAI
CTO last year

Perplexity



Aravind Srinivas
was a research
scientist at OpenAI for
a year until 2022

200+

former
employees have
established their
own startups

Mustafa
Suleyman
CEO of
Microsoft
AI, was co-
founder of
DeepMind

स्रोत: IE